



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062020-219833
CG-DL-E-09062020-219833

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1617]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2020/ज्येष्ठ 19, 1942

No. 1617]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2020/JYAISHTHA 19, 1942

गृह मंत्रालय

(काउंटर टेरोरिज्म एण्ड रेडिकलाइजेशन डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2020

का.आ. 1800(अ).—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1391 (अ.), तारीख 25 मई, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, श्री अवधुत मधुकर चिमालकर को, महाराष्ट्र राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित विचारण न्यायालयों में और अपील न्यायालय अथवा पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष ऐसे मामलों से उद्भूत अपीलों, पुनरीक्षण या अन्य मामलों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संस्थित मामलों के संचालन के लिए इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009/एनआईए]

आशुतोष अग्रिहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Counter Terrorism & Counter Radicalization Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2020

S.O. 1800(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, vide number S.O. 1391 (E), dated the 25th May, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints Sh. Avadhut Madhukar Chimalkar as Special Public Prosecutor (SPP) for conducting the cases instituted by National Investigation Agency in the trial courts and appeals, revisions or other matters arising out of such cases in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Maharashtra for three years with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. 11034/30/2009/NIA]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.